“सच्ची खोज अच्छी खबर”

ज्ञान सरोवर

R.N.I.Reg.No.MAHHIN/2009/27377 (हिन्दी साप्ताहिक) डाक पंजीकरण संख्या- MH/MR/North East/237/2012-14

वर्ष : 16 अंक : 28 (प्रत्येक गुरूवार) मुम्बई, 25 जुलाई से 31 जुलाई, 2024 पृष्ठ : 8 मूल्य : 2.00 रूपये

एक्शन में सीएम योगी, लापरवाह पांच एडीएम एफआर और तीन एसडीएम से जवाब तलब

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इसमें पांच जिलों के एडीएम एफआर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, जबकि तीन एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया। सीएम ने सभी लापरवाह अधिकारियों को दो दिनों में अपना स्पष्टीकरण शासन के सौंपने के निर्देश दिये हैं। बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आपदा से हुई जनहानि का मुआवजा 24 घंटे के अंदर प्रदान किया जाए। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में आपदा से हुई जनहानि का सर्वे पूरा कर 24 घंटे में मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुई जनहानि और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इनमें बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फनगर के एडीएम एफआर क्रमशः संतोष सिंह, उमेश चंद्र निगम, उमा शंकर, एस सुधाकरन और गजेंद्र कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि सौंपी गयी है। इसके साथ ही लापरवाही पर सिद्धार्थनगर की सदर तहसील के एसडीएम ललित कुमार मिश्रा, हाथरस की शादाबाद तहसील के एसडीएम संजय कुमार सिंह और अलीगढ़ की अतरौली तहसील के एसडीएम अनिल कुमार कटियार से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ अश्विनी कुमार को निलंबित कर दिया है। सभी को दो दिनों के अंदर अपना जवाब शासन को सौंपना होगा।

वाईएमसीए को पूरे अंक

प्रयागराज। वाईएमसीए ने आशीष नेहरा क्रिकेट क्लब को तीन विकेट से हराकर रविकांत अंडर–16 समर लीग में पूरे अंक प्राप्त किये। दौलत हुसैन कॉलेज मैदान पर मंगलवार को खेले गए मैच में आशीष नेहरा क्रिकेट क्लब ने 23.3 ओवर में 145 रन (आनंद कुमार 67, अंशुमान 28, देवांश शर्मा 4/30, लक्ष्य यादव 2/47) बनाये। जवाब में वाईएमसीए ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन (सत्यम यादव 38, लक्ष्य यादव 30, राहुल कुमार 2/49, आनंद कुमार 2/50) बना लिए। मैच में अजय कुमार व तौसीफ शेख अंपायर और मोहम्मद सैफ स्कोरर रहे।

क्या है जीएम सरसों विवाद, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्प्लिट जजमेंट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की पर्यावरण संरक्षण के लिए विमोचन पर एक खंडित निर्णय दिया। दो–न्यायाधीशों की पीठ ने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) को लेकर केंद्र सरकार को कड़े और पारदर्शी जैव–सुरक्षा प्रोटोकॉल पर एक राष्ट्रीय नीति लाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के फैसले ने जीएम सरसों, डीएमएच–11 की पर्यावरणीय रिहाई की अनुमति देने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के इस निर्णय ने जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और कृषि पद्धतियों पर जीएम फसलों की सुरक्षा, आवश्यकता और संभावित प्रभाव पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। न्यायमूर्ति नागरत्ना के अनुसार, प्रभावी परामर्श की कमी और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के सिद्धांतों की उपेक्षा के आधार पर निर्णय ख़राब हो गया था। न्यायाधीश ने जीएम सरसों की सशर्त रिहाई के फैसले को जीईएसी से मंजूरी दिलाने में अनुचित जल्दबाजी दिखाने के लिए भी केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का पर्याप्त आकलन करने में विफलता अंतर–पीढ़ीगत समानता का गंभीर उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि जीईएसी ने अक्टूबर 2022 में जीएम सरसों पर जिस तरह से निर्णय लिया, उसमें उन्हें मनमानी या अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर सभी उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया जा सका। किसी भी प्रक्रियात्मक अंतराल को इंगित करें, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। जीएम सरसों की पर्यावरणीय रिहाई पर असहमति के बावजूद, पीठ जीएमओ पर एक राष्ट्रीय नीति के महत्व को रेखांकित करने में स्पष्ट थी। इसने केंद्र सरकार को राज्यों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और किसान निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद जीएमओ पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने का निर्देश दिया।

बजट में भेदभाव के आरोप पर वित्त मंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब, बोलीं, भाषण में हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं

नई दिल्ली। विपक्ष के भेदभावपूर्ण केंद्रीय बजट के विरोध के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सरकार के रुख का बचाव किया और बजटीय निर्णयों के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया। अपने भाषण के दौरान, सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि हर बजट घोषणा में हर राज्य का उल्लेख करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बजट में, आपको लेने का मौका नहीं मिलता।

कैबिनेट ने वडावन पर एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र खुद को उपेक्षित महसूस करता है? वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश के हर राज्य का नाम यदि भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों में नहीं जाते हैं? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का लोगों को यह आभास देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है कि हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है। यह एक अपमानजनक आरोप है। भेदभावपूर्ण बजट पर विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने से पहले, विपक्ष के नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये कुर्सी बचाने के लिए ये सब हुआ है... हम इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल विरोध करेंगे। अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?

राज्यसभा में आज एक नाटकीय घटनाक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे ही केंद्रीय बजट पर अपना भाषण देने के लिए उठीं, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री ने सदन को संबोधित करना शुरू ही किया था कि विपक्षी सांसद एकजुट होकर अपनी सीटें खाली छोड़कर सदन से बाहर चले गए।

सीएम योगी बोले- बजट में अंत्योदय की पावन भावना..., अखिलेश बोले-नाउम्मीदी का पुलिंदा है

लखनऊ । केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी आम बजट 2024-25, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्राविधानों की घोषणा स्वागत योग्य है। नए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक-कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं मा. केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय बजट 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट भी पुराने ढर्रे पर है। ये बजट अच्छे दिन की उम्मीद वाला कम और मायूस करने वाला ज्यादा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि संसद में आज पेश केन्द्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा?

उन्होंने कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूलभुलैया वाला न हो बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे और आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति-जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया

है। युवाओं, महिलाओं और नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपए सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपए की मदद और शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एवं 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट शानदार, जानदार है। यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है...। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह औसत, अर्थहीन, भ्रामक और दीर्घकालिक दृष्टि के अभाव वाला बजट है। देश के सर्वाधिक आबादी वाले सूबे को इस बजट ने निराश किया है।

शिंदे ने विदार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए छह महीने का समय दिया

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंजीनियरिंग,

मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु छह महीने का समय देने का फैसला लिया। अब विद्यार्थियों को वर्ष 2024-25 के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन दाखिल करने की तारीख से छह महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विशेष रूप से मराठा समुदाय के छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) 2024 के लिए आरक्षण अधिनियम 20 फरवरी को एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी तथा अर्ध-सरकारी नौकरियों में सीधी सेवा भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसका मुख्य रूप से मराठा समुदाय को लाभ हुआ है। एसईबीसी अधिनियम का लाभ लेने वाले छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण एसईबीसी छात्र जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विस्तार की मांग कर रहे थे। इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा को छह महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

लखनऊ से कानपुर के लिए जल्द दौड़ेगी वंदे मेट्रो, गोमती नगर से भोपाल के लिए चलेगी वंदे भारत

लखनऊ (संवाददाता)। कानपुर के लिए लखनऊ से सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे मेट्रो जल्द पटरी पर उतर सकती है। अफसरों को इसके लिए रेल बजट में 240 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। ऐसे ही गोमतीनगर से भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, कटरा व पुरी के लिए नई ट्रेन की सौगात यात्रियों को मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को पेश किए गए आम बजट में रेलवे के लिए कुल 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें सेफ्टी व मेंटेनेंस के मद में 1.08 लाख करोड़ दिए गए हैं। लखनऊ मंडल में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए आवंटित की गई रकम की जानकारी अगले सप्ताह पिंक बुक जारी होने पर मिलेगी। आला अफसरों को उम्मीद है कि लखनऊ से कानपुर के बीच वंदे मेट्रो चलाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए रूट के स्टेशनों की इंटरलॉकिंग, ट्रैक मेंटेनेंस आदि पहले ही हो चुका है। रूट पर ट्रैक स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। कानपुर के लिए चलने वाली वंदे मेट्रो की स्पीड 130 से 160 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। इससे कानपुर की दूरी महज 45 मिनट में पूरी कर ली जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, गोमतीनगर से भोपाल के लिए वंदे भारत शुरू करने की भी तैयारी है। पुरी व कटरा के लिए ट्रेन शुरू करने का प्लान पहले से है। उत्तर रेलवे के चारबाग स्टेशन के अपग्रेडेशन का काम कराया जा रहा है। सेकेंड एंट्री बन रही है।

जल्द एयर कॉन्कोर्स का निर्माण शुरू किया जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए 450 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। बजट में इसके लिए रकम मिलने से काम से तेजी आएगी। अमृत भारत स्टेशनों के विकास को भी गति मिलेगी। चारबाग से दिलकुशा व आलमनगर की ओर फोरलेन आउटर बनाया जाना है। दिलकुशा आउटर के लिए काम शुरू हो चुका है। फोरलेन आउटर बन जाने से ट्रेनों को आउटर पर नहीं रोकना पड़ेगा। इससे इनकी लेटलतीफी घटेगी। लखनऊ मंडल में ट्रेन हादसे रोकने के लिए सेफ्टी व यात्रियों की ट्रेनों में सुरक्षा पर खासा खर्च होगा। इसके लिए सौ करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। इससे सीसीटीवी कैमरों से लेकर हैंड हेल्ड मशीनें, लगेज स्कैनर, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाएगा।

आठ घंटे गुल रही कजियारा फीडर की बिजली

सीतापुर। पुराने सीतापुर उपकेंद्र से जुड़े कजियारा फीडर की बिजली आपूर्ति मंगलवार को आठ घंटे गुल रही। लंबी कटौती के चलते उपभोक्ता गर्मी में बेहाल रहे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होने के साथ पेयजल संकट खड़ा हो गया। करीब 50 हजार की आबादी प्रभावित हुई। इस फीडर से जुड़े मोहल्लों में सुबह 10 बजे कटौती कर दी गई। तीन से चार घंटे में इनवर्टर डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। राहत पाने के लिए घर के बाहर टहलते रहे। दोपहर के समय नगरपालिका की ओर से पेयजल सप्लाई भी बाधित हुई। मोहल्ले में लगे हैंडपंप के जरिए लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी कीं। इस इलाके में कारखाने भी ठप रहे। कार्यालयों के बाहर जनरेटर चलते हुए नजर आए। शाम छह बजे के बाद आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

पांच साल के लिए मजबूत नींव रखता बजट, राहत के साथ प्रोत्साहन का भी बनेगा आधार

वर्ष 2024 का बजट अत्यधिक प्रत्याशित रहा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद कि पिछला दशक आने वाले पांच वर्षों में अपेक्षित परिवर्तनकारी

परिवर्तनों के लिए केवल एक प्रस्तावना या श्ट्रेलरश था। यह बजट नौ प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संरचित है, जिसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है, जो सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए श्अच्छी भुगतान वाली नौकरियांश निर्मित करने की अपनी प्राथमिकता में काफी स्पष्ट रही है। इस संबंध में, शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन दूरगामी प्रभाव वाला एक रणनीतिक कदम है। दूसरी तरफ, कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य दूरगामी सोच वाले दृष्टिकोण को दर्शाते हुए उत्पादकता बढ़ाना है। एक और उल्लेखनीय पहल रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन कार्यक्रम है, जहां सरकार भविष्य निधि में नियोक्ता का हिस्सा और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नए कर्मचारियों के लिए पहले महीने का वेतन, जो पंद्रह हजार रुपये तक हो, कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। कार्यबल में महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन और शिक्षा ऋण की ब्याज दरों में तीन प्रतिशत की छूट समावेशी विकास की दिशा में सराहनीय कदम हैं। इसके अलावा, सरकार ने एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है जिसका लक्ष्य एक करोड़ भारतीय युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में आवासीय और व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को कम किया जा सके। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राजनीति में विश्वस्त सहयोगी होने के नाते स्वाभाविक भी था। बिहार के लिए, कोसी नदी बेसिन में बाढ़ सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बजट क्रेडिट गारंटी योजना को बढ़ाना और मुद्रा लोन सीमा को रुपये 20 लाख तक बढ़ाने जैसे उपायों से एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलने, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बजट में शहरी विकास को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है, जिसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं परिवहन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कई सुधारों के प्रस्ताव के साथ सरकार ने शहरी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो सतत विकास एवं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत का भविष्य शहरी क्षेत्रों पर ही निर्भर है। बजट में ऊर्जा परिवर्तन को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसमें सोलर रूफटॉप नीति की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की फंडिंग के लिए एक लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो नवाचार के महत्व को रेखांकित करता है। बजट में रोजगार, भूमि संबंधी मामलों और वित्तीय क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा पेश की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना है। बजट प्राप्तियां बढ़कर 32.07 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, जबकि राजकोषीय घाटा जो अंतरिम बजट में 5.1 फीसदी था, वह घटकर 4.9 फीसदी रह गया है। यह कमी मुख्य रूप से जीडीपी में वृद्धि, उच्च प्राप्तियों और कम व्यय के कारण आई है। 2023–24 के वास्तविक खातों से पता चलता है कि संशोधित बजट में निर्धारित 5.8 फीसदी की तुलना में राजकोषीय घाटा घटकर 5.6 फीसदी रह गया है। बजट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में कई तरह के बदलाव लाता है। हालांकि अप्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से जीएसटी का सरलीकरण एक सकारात्मक कदम है। लेकिन कर कटौती एवं उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दे अब भी हैं। कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी से शेयरबाजार में सूचीबद्ध निवेशकों के लिए चिंताएं बढ़ी हैं। सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध, दोनों प्रतिभूतियों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को एक समान 12.50 फीसदी रखकर दोनों के बीच के अंतर को पाट दिया है। यह गैर–सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए दर में बड़ी कमी है, जिससे स्टार्ट–अप्स में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। सोना एवं चांदी पर कर घटाकर छह फीसदी कर दिए जाने से इनकी तस्करी तो घटेगी ही, मूल्यवर्धन एवं निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एंजल टैक्स हटाने से स्टार्ट–अप को भी बड़ी राहत मिली है। व्यक्तिगत कराधान के मामले में बजट ने कई लोगों को निराश किया है। जबकि प्रति व्यक्ति 17,500 रुपये की सकल कटौती के साथ कुछ कर राहत दी गई है। कर संरचना के छह स्लैब को बनाए रखना शायद अनावश्यक रूप से जटिल है। तीन–स्लैब की संरचना अधिक सरल होती। बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत का उद्देश्य कुछ लंबित आयकर विवादों को हल करना है। प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह अधिक प्रभावी होता, यदि उच्च न्यायालय के निर्णयों का बेहतर सम्मान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए सीमा कम से कम 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जाती। कुल मिलाकर, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आगामी पांच साल के लिए ठोस नींव रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में राहत और प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें रोजगार सृजन, शहरी विकास और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि, बजट मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है, जो लगातार कर बोझ उठाता है। पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि इक्विटी संस्कृति को भी कम कर सकती है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

मीडिया को न तो प्रतिबंधित किया, ना बाहर निकलने का आदेश

रूस की सरकार ने अपने यहाँ किसी भी मीडिया को न तो प्रतिबंधित किया, ना बाहर निकलने का आदेश दिया। सिर्फ ब्लादीमीर पुतिन ने कानून बना दिया कि जो भी मीडिया हाउस बिना किसी तथ्य के फेक न्यूज़ प्रसारित करेगा उसे एक महीने का वक्त दिया

जाएगा ताकि वह साबित कर सके कि यह न्यूज़ सच है अन्यथा 15 साल की जेल होगी। इस कानून के बनने के बाद बीबीसी, डॉयचे वेले, अल जजीरा, सीएनएन, वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स के सभी पत्रकार अपना बोरिया–बिस्तर समेट कर रूस छोड़कर भाग गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया ही नहीं तब इन्होंने रूस क्यों छोड़ दिया ?? इन सभी मीडिया हाउसेस का रूस छोड़ना इस बात का सुबूत है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाते हैं। फेक न्यूज़ फैलाते हैं वरना यदि इन्हें अपने न्यूज़ पर भरोसा होता तो यह रूस में डटे रहते। भारत में भी ऐसा कानून अति आवश्यक है...

–हिंसक हिंदू

बजट को लेकर टेक्सटाइल सेक्टर को काफी उम्मीदें

मुंबई। संसद में मंगलवार को आम बजट (बजट 2024) पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। बजट को लेकर टेक्सटाइल सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। हिंदुस्तान चौंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुशील गादियान ने बजट से उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा श्रम प्रधान उद्योग है। कृषि के बाद भारत में कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। सरकार से उम्मीद है कि कपड़ा उद्योग को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कपड़ा उद्योग पर ध्यान दे तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार काफी हद तक बढ़ सकता है। भारत कपड़ा निर्यात में चीन, वियतनाम और श्रीलंका से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां श्रम, बिजली और ब्याज दरें बहुत महंगी हैं। सरकार की नीति के कारण हम अपनी इच्छा के अनुसार निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन सभी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी, तब तक हमारा निर्यात नहीं बढ़ेगा। सरकार को प्रोसेस हाउस में कपड़ों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू बाजार में मांग की तुलना में आपूर्ति बहुत अधिक है। भुगतान नहीं के कारण बहुत सारा माल बिक नहीं पाता। आज के समय में एमएसएमई सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। अगर सरकार एमएसएमई पर ध्यान देगी, तभी घरेलू बाजार चल पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के अटके हुए भुगतान की वसूली के लिए कानून तो बना दिया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 6–7 साल तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। सरकार के कानून मंत्री को इस मामले पर काम करना चाहिए।

सम्पादकीय...

पांच साल का दूसरा कार्यकाल हासिल

सब कुछ वैसा ही हुआ, जैसा सोचा जा रहा था। उर्सुला वॉन डेर लेन ने फिर से यूरोपीय आयोग यानी ईसी के अध्यक्ष के रूप में पांच साल का दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। यूरोपीय संसद ने 284 के मुकाबले 401 वोट से उनके नाम पर मुहर लगाई। 15 सदस्य गैरहाजिर रहे। अब तक ईसी का कोई अध्यक्ष दूसरी बार निर्वाचित नहीं हुआ था। हालांकि उनकी राह में बाधाएं थीं। 27 ईयू नेताओं का समर्थन उनको पहले से हासिल था। लेकिन यूरोपीय संसद के अनुमोदन की उन्हें आवश्यकता थी। और वहां हालात उनके अनुकूल नहीं थे। लेकिन गुरुवार को हुए मतदान में उन्होंने वहां अनुमोदन हासिल कर लिया। उर्सुला, जो एक जर्मन राजनेता हैं, को गुरूवार को होने वाले मतदान में संसद के 720 सदस्यों में से आधे से ज्यादा, मतलब कम से कम 361, के समर्थन की जरुरत थी और उनको 401 वोट मिले। तीन राजनीतिक समूहों के समर्थन की उम्मीद उनको पहले से थी। इन तीनों को संयुक्त रूप से पिछले महीने हुए चुनाव में बहुमत हासिल हुआ था और इन समूहों ने 2019 में भी उनका समर्थन किया था। ये हैं उनकी स्वयं की मध्य–दक्षिणपंथी यूरोपियन पीपुल्स पार्टी या ईपीपी, जिसकी 188 सीटें हैं, सोशलिस्ट, जिसकी 136 सीटें हैं और उदारवादी रिन्यू, जिनकी 77 सीटें हैं। लेकिन राजनीतिक उठापटक जोरों पर थी। तीनों समूहों के कई सांसदों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वॉन डेर लेन का समर्थन नहीं करेंगे। इनमें ईपीपी समूह की फ्रांस की रूढ़िवादी कंजरवेटिव रिपब्लिकन पार्टी, जर्मनी, आयरलैंड और रोमानिया के उदारवादी तथा फ्रांस और इटली के सोशलिस्ट और कुछ अन्य सांसद शामिल थे। साथ ही, चूंकि मतदान गोपनीय होता है इसलिए इस बात की भी संभावना थी कि कुछ सांसद सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करेंगे मगर स्ट्रासबर्ग में मतदान के समय श्नोच का बटन दबाएंगे। असल में सैद्धांतिक तौर पर अधिकांश देशों के नेता उर्सुला वॉन डेर लेन को पसंद करते हैं। उन्होंने कई देशों द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए ऋण से पोस्ट पैनडेमिक रिकवरी फंड बनाकर दक्षिण यूरोपीय देशों को संतुष्ट कर दिया, वहीं उत्तरी यूरोप के देशों की क्लाइमेट चेंज सम्बंधी चिंताओं की ओर भी ध्यान दिया। पूर्वी यूरोप के देश, यूक्रेन के प्रति उनके दृढ़ समर्थन से खुश हैं। जर्मनी के ओलाफ स्कोल्ज, विरोधी पार्टी के होने के बावजूद अपनी हमवतन का समर्थन करेंगे। जो एकमात्र नेता उनकी जबरदस्त खिलाफत करते आ रहे हैं वे हैं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान। कई नेता कुछ अन्य मुद्दों के चलते उर्सुला वॉन डेर लेन के खिलाफ हैं, जैसे पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, जो उनके ही समूह के हैं लेकिन जिन्हें हाल में उनके द्वारा करवाया गया अप्रवासियों संबंधी समझौता पसंद नहीं आया। स्पेन के पेड्रो सांचेज भी उनके इजराइल समर्थक रवैए के कारण उनके खिलाफ हैं। परंतु उर्सुला में विचारधारात्मक दृढ़ता का अभाव उन्हें खतरनाक बनाता है। सन 2019 में ईयू के नेता यूरोपीय संसद पर उन्हें इसलिए थोप सके थे क्योंकि उस समय वे एक अनजान व्यक्ति थीं। मगर अब ऐसा नहीं है। ईसी में अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जलवायु सम्बंधी मुद्दों सहित अन्य मामलों में वामपंथ की ओर झुकाव दिखाया। मगर फिर वे दक्षिणपंथ की ओर झुक गईं और उन्होंने ईयू की अप्रवासी नीति में अप्रवासियों को रवांडा रवाना करने जैसी योजनाओं का समर्थन किया। उनके गुण और उनकी कमियां सबके सामने हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी कमियां सामने आईं तो रूस के यूक्रेन पर हमले के मामले में उनके गुण। उर्सुला निरूसंदेह यह दावा कर सकतीं हैं कि उन्होंने कई सफलताएं हासिल की हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनका अधिकांश कार्यकाल संकटों का मोचन करने में बीता। वे हर संकट पर प्रतिक्रिया देती रहीं हैं और कई मामलों में उन्होंने संकट से निपटने की ज़िम्मेदारी यूरोपीय आयोग में शामिल विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं पर छोड़ दी, जिससे आयोग के अध्यक्ष चार्ल्स मीशेल से उनकी प्रतिद्वंदिता हो गई। यह उनके लिए नुकसानदायक है। फिर दुनिया में चल रहे दो युद्धों के मामले में उनका रुख का मसला भी है। वे यूक्रेन के मामले में जेलेंस्की का समर्थन कर रही हैं मगर गाजा युद्ध के मामले में वे पूरी तरह नेतन्याहू के साथ हैं। इस कारण भी उनकी आलोचना हुई। मगर दुनिया और उनके पुनर्निर्वाचन के बारे में व्याप्त अनिश्चितता से उन्हें फायदा हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वापसी की सम्भावना है, यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, यूरोप में अति–दक्षिणपंथियों का दबदबा बढ़ रहा और एक आर्थिक ताकत के रूप में यूरोपीय संघ कमजोर हो रहा है। ऐसे में यूरोप एक नए नेता को चुनने की जोखिम नहीं ले सकता था। तभी इस बात की काफी सम्भावना थी कि उर्सुला वापस आ जाएंगी। मगर इससे ईयू के अंदर व्याप्त अनिश्चितता और असंतोष खत्म नहीं होगा।

आम बजट से आम आदमी फिर ठगा गया

मोदी सरकार के तीसरे शासन काल का पहला आम बजट 23 जुलाई को संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।आम चुनाव के बाद का यह पहला आम बजट था।पक्ष वाले इसे शानदार संतुलित व विकासोन्मुखी बजट बता रहे हैं।तो विपक्ष वाले सरकार बचाने वाला बजट बता रहे हैं।मगर इस आम बजट में आम आदमी को क्या मिला,न पक्ष बता रहा है न विपक्ष।पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है।और विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है।जो उसका सिद्धांत है।जिस पर वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है।चुनाव सभी आम आदमी को आगे रखकर लड़ते हैं।मगर चुनाव के बाद आम आदमी को इतना पीछे रखते हैं कि वह सीढ़ी लगाने के बाद भी नहीं दिखता।जैसा कि इस बार के बजट से भी दिख रहा है।सभी सेक्टर के लिए तमाम योजनायें तो दिख रही हैं।मगर आम आदमी के लिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं है इस आम बजट में भी।

इस आम बजट में वह वस्तुएं सस्ती हुई हैं जो रोजमर्रा की नहीं हैं।वो वस्तुएं सस्ती नहीं हुई जो रोजमर्रा की हैं।जिससे आम आदमी रोज दो चार हो रहा है।आम आदमी के रोजगार की बात न के बराबर है।खाने पीने की वस्तुएं जस की तस बनी हुई हैं।तेल और गैस का भाव अपने उच्च स्तर पर ही बना हुआ है।जिससे आम आदमी की आज कमर टूट रही है।न कायदे का रोजगार देने की बात हुई है न मंहगाई कम करने की बात इस बजट में हुई है। सुलभ व सुरक्षित यात्रा की बात इस बजट में भी नहीं की गई है।इस आम बजट से अम आदमी खास करके मध्यमवर्ग एकबार फिर ठगा सा महसूस कर रहा है।हर बार की तरह इस बार भी जो मन में मंहगाई का भय था।इस आम बजट में भी कुल मिलाकर वही है।

रोजगार के नाम पर लालीपाप ही जनता को हर बार दिया जाता है। मोदी सरकार की मुद्रा लोन बेरोजगारों बेसहारों को सहारा देने की महत्वाकांक्षी योजना 2014 से बड़े जोर शोर से चलाई जा रही है।इस योजना के लाभार्थियों को बिना गारंटी के दस लाख लोन देने की बात मोदी सरकार ने की थी,और आज भी कर रही है।मगर इस लोन का लाभार्थी आज तक अपने पास पड़ोस व दूर दराज तक का कोई मिला नहीं। यह भी एक सफेद हाँथी जैसा ही है।सरकार कहती है मुद्रा योजना का लाभ उन बेरोजगारों को मिलेगा जिनके पास या तो रोजगार नहीं है,या है तो नाकाफी है।उनके सहयोग के लिए बिना गारंटी व गारंटर के यह लोन दिया जायेगा।बैंक कहती है पहले दस हजार बैंक में जमा करो। इसके बाद छ महीने का ट्रांजेक्शन यानी बैंक से लेन देन करो और अपना व्यापार दिखाओ, जिससे दस बीस हजार का उत्पादन हो रहा हो, वह दिखाओ।तब मिलेगा।इतना बड़ा विरोधाभास है सरकार की इस योजना में।और बहुत बड़ा छल है जनता के साथ।फिर भी मोदी सरकार आज भी उसी मद में वित्त रखके लोगों उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने पर तुली है।

> *आम आदमी की आज कमर टूट रही है न कायदे का रोजगार देने की बात हुई है न मंहगाई कम करने की बात इस बजट में हुई है। सुलभ व सुरक्षित यात्रा की बात इस बजट में भी नहीं की गई है।इस आम बजट से अम आदमी खास करके मध्यमवर्ग एकबार फिर ठगा सा महसूस कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी जो मन में मंहगाई का भय था।इस आम बजट में भी कुल मिलाकर वही है।*

आज यदि पक्ष और विपक्ष की तरफ से जनता को सबसे अधिक ठगा जा रहा है तो, वह है रोजगार।पक्ष दस रोजगार देकर ऐसा प्रचारित कर रहा है जैसे बेरोजगारी खतम कर दिया।विपक्ष ऐसा प्रचारित कर रहा है जैसे किसी के पास रोजगार है ही नहीं।जबकी बेरोजगारी के लिए दोनो ही जिम्मेदार है।जो विपक्ष आजके आम बजट को रोजगार विरोधी बता रहा है।वही जब शासन में थे तब क्यों नहीं दिए।देना तो छोड़ो उनके ही शासन की गलत नीतियों के चलते तमाम मिलें फैक्टरियाँ बंद हो गई।

जिसके चलते बेरोगारी बढ़ती गई और रोजगार घटते गये।जनसंख्या बढ़ती गई।यदि विगत सरकारों ने कुछ ढंग के काम किए होते तो आज के बजट पे रोजगार पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।लगभग सन दो हजार तक दसवीं पास को सिपाही की नौकरी मिल जाती थी।पर विगत की सरकारों ने कुंठा बस इसे बढ़ाकर बारहवीं पास कर दिया।जिसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ गई है।आज वही विपक्ष में बैठकर बेरोजगारी पर बहस कर रहे हैं।तब का विपक्ष भी आज बेरोजगारी कम करने से बचता फिर रहा है।और बहानेबाजी कर रहा है।रोजगार उपलब्ध कराने के वजाय प्रचार में अधिक लिप्त है।और आम आदमी हताश और त्रस्त है बर्तमान और पूर्व की सरकारों की करतूँतों से।

कुल मिलाकर यह आम बजट भी मध्यम वर्ग विरोधी ही है।इस आम बजट से सबको तो कुछ न कुछ मिला।मगर आम आदमी खासकर मध्यम वर्ग हमेशा की तरह फिर से ठगा ही गया है।विपक्षियों का कहना भी सही है कि यह बजट सरकार बचाने वाला है।सरकार ने वस्तुएं सस्ती करने की वजाय प्रलोभन की व्यस्था अधिक किया है।जो की नहीं होना चाहिए था।सरकार को सब्सिडी भी गरीब मजदूर वर्ग के लिए रखनी चाहिए,वह भी नहीं किया।मुफ्तखोरी से बचना चाहिए,वह भी नहीं किया।मंहगाई पर तो बात ही नहीं की है।जो वस्तुएं वर्ष में एक बार खरीदी जायेंगी,उसको सस्ती करके क्या फायदा।सस्ती तो खा। वस्तुएं होनी चाहिए,जो सबके पेट से जुड़ी है।उस पर वित्त मंत्री महोदया ने कुछ काम ही नहीं किया हैं।इस आम बजट से आम आदमी रोये की हंसे।सस्ती एक्सरे मशीन मोबाईल आदि हुए हैं,मगर उनकी सेवा लेने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।क्योंकि न तो आम आदमी को मोबाईल का रिचार्ज यानी मोबाईल से बात करना सस्ता होगा।न ऐक्सरे का पैसा कम देना पड़ेगा।इस आम बजट से आम आदमी को पूरी तरह बेवकूफ बनाने का काम सरकार ने किया है।सोना चाँदी का दाम रोज घटता बढ़ता रहता है।उसे सस्ता करके सरकार क्या जतलाना चाहती है।क्या लोग सोना चाँदी खायेंगे।कुल मिलाकर आम बजट से आम आदमी खासकर मध्यम वर्ग इस बार भी ठगा ही गया है।

–पं.जमदग्निपुरी

मानसूनी बुखार और डेंगू दोनों के बढ़ने लगे मामले, जानिए इनमें कैसे करें अंतर

बरसात का मौसम शुरू होते ही कई तरह की बीमारियों के मामले भी बढ़ने लग गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, इन दिनों में सबसे ज्यादा खतरा मच्छरजनित रोगों का होता है। बरसात का समय मच्छरों के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होता है, यही कारण है कि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि गर्मी से बरसात का बदलता समय मौसमी बुखार के जोखिमों को भी बढ़ा देता है। इस लेख में हम मौसमी बुखार और डेंगू के बारे में जानेंगे। इन दोनों ही बीमारियों के ज्यादातर लक्षण चूंकि एक जैसे ही होते हैं, ऐसे में अक्सर लोगों के लिए इनमें अंतर कर पाना काफी कठिन हो जाता है। मौसमी बुखार के लक्षण वैसे तो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं हालांकि डेंगू पर अगर ध्यान न दिया जाए तो इसके कारण रक्तस्रावी समस्याओं का जोखिम हो सकता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

गुरुग्राम स्थित एक अस्पताल में कंसल्टेंट डॉ मुकेश सिन्हा बताते हैं, वैसे तो अभी अस्पतालों में डेंगू के मामले नाम मात्र के हैं, हालांकि बरसात का मौसम बढ़ने के साथ इसके जोखिम भी बढ़ सकते हैं। मौसमी बुखार और फ्लू की समस्या इन दिनों जरूर अधिक देखी जा रही है। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनमें एक साथ मानसूनी बुखार या डेंगू दोनों हो सकते हैं। दोनों बीमारियों के लक्षण शुरुआत में लगभग एक जैसे ही होते हैं। डेंगू की स्थिति में जल्द इलाज की जरूरत होती है।

मानसून में होने वाले बुखार की समस्या

मानसूनी बुखार, बारिश के मौसम में होने वाले वायरल संक्रमण के कारण होता है। मौसम में होने वाले बदलाव के साथ इंफ्लूएंजा जैसे वायरस के संक्रमण की स्थिति में आपको हल्का से लेकर तेज बुखार, नाक बहने या बंद होने, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान, हल्का सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मानसूनी बुखार आमतौर पर धीरे–धीरे शुरू होता है और अक्सर खांसी या जुकाम जैसे श्वसन संबंधी लक्षणों के साथ होता है।

डेंगू बुखार की समस्या

डेंगू बुखार भी संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। डेंगू के मच्छर दिन के समय में अधिक संक्रिय रहते हैं इसलिए मच्छरों को काटने से बचाव के उपाय करते रहना सबसे जरूरी माना जाता है। डेंगू वायरस से संक्रमित हर व्यक्ति में लक्षण अलग–अलग हो सकते हैं। इसमें बुखार के साथ–साथ मतली, उल्टी, शरीर पर चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। गंभीर स्थितियों में डेंगू के कारण आंतरिक रक्तस्राव होने का जोखिम भी बढ़ जाता है।

इन दोनों में कैसे करें अंतर?

मानसूनी बुखार और डेंगू इन दिनों दोनों ही रोग के मामले बढ़ रहे हैं और इनके ज्यादातर लक्षण भी एक जैसे ही होते हैं, इसलिए कुछ अंतरों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। डॉ मुकेश बताते हैं, दोनों में बुखार, दर्द और थकान होती है, पर डेंगू में आम तौर पर ये अचानक शुरू होता है और लक्षण बढ़ने के साथ गंभीर शरीर दर्द और चकत्ते होने लगते हैं। डेंगू बुखार के कारण ब्लड प्लेटलेट काउंट में कमी आने लगती है जबकि मानसूनी बुखार में ऐसे दिक्कत नहीं देखी जाती है। इन दोनों का उपचार भी अलग तरीकों से किया जाता है। मानसूनी बुखार के ज्यादातर मामले आराम करने और शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ ओवर–द–काउंटर बुखार दवा (पैरासिटामोल) से ठीक हो जाते हैं जबकि डेंगू के इलाज में कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। अगर किसी को 3–4 दिनों तक बुखार के साथ दर्द रहता है और सामान्य उपायों से आराम नहीं मिल रहा है तो समय रहते खून का जांच कराना आवश्यक हो जाता है।

1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा, श्सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।य सीतारमण ने कहा, श्महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा।

राधिका मदान को क्यों हो रहा इरफान खान से बात न करने का पछतावा? कहा- वह बहुत कुछ झेल रहे थे

नई दिल्ली। इस बात में कोई शक नहीं है कि राधिका मदान हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा हैं। डेली सोप मेरी आशिकी तुम से ही से लाइमलाइट बटोरने के बाद राधिका ने फिल्मी दुनिया में जलवा बिखेरा। उन्होंने पटाखा, मर्द को दर्द नहीं होता और शिद्दत जैसी फिल्मों में काम किया है। राधिका मदान को साल 2020 में आई फिल्म अंग्रेजी मीडियम से लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म में वह इरफान खान की बेटी के किरदार में दिखी थीं। दिग्गज अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करना राधिका के लिए बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक बात का पछतावा है। राधिका मदान ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इरफान खान से अंग्रेजी मीडियम के सेट पर बात न करने का पछतावा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में राधिका ने कहा, मैं हाल ही में अपने दोस्त को यह फिल्म दिखा रही थी, क्योंकि उसने इसे नहीं देखा था और मैं सोचती रही कि क्या मैं फिर कभी ऐसी फिल्म कर पाऊंगी। मुझे इरफान सर की याद आ रही थी। फिल्म के सेट पर सरफिरा एक्ट्रेस का पूरा ध्यान अपने कैरेक्टर पर था। उन्हें लगा कि शूट के बाद वह कभी इरफान संग बात करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधिका ने कहा, मैं सोच रही थी कि मैंने उनसे ज्यादा बात क्यों नहीं की और उनसे चीजें क्यों नहीं निकलवाईं। मैं सेट पर बहुत शांत रहती थी और उन्हें स्पेस देने की कोशिश करती थी। मेरा ध्यान अपने कैरेक्टर पर था। मुझे लगा कि फिल्म के बाद मेरे पास उनके साथ फिल्मों, अभिनय और क्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए बहुत समय होगा, लेकिन वह बहुत कुछ झेल रहे थे। मालूम हो कि अंग्रेजी मीडियम की रिलीज के डेढ़ महीने बाद ही इरफान खान का कैंसर से निधन हो गया था।

गांधी–अंबेडकर डिबेट पर बयान देकर घबरा गई थीं जाह्नवी कपूर, कहा– यह थोड़ा जोखिम भरा है

नई दिल्ली। बी–टाउन में बहुत कम स्टार्स हैं, जो राजनीति से जुड़े मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। इसी साल मई में जब जाह्नवी कपूर ने गांधी–अंबेडकर डिबेट पर बात की तो लोग हैरान रह गये। जाह्नवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी–अंबेडकर का डिबेट देखना दिलचस्प होगा। जाह्नवी कपूर के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरीं। राजनीति से जुड़ी इतनी गहरी बात उनके मुंह से सुनकर लोग हैरान रह गये। लोगों ने कहा कि जाह्नवी को इस मुद्दे पर बोलने के लिए उनकी पीआर टीम ने ट्रेन्ड किया है। हालांकि, ऐसा नहीं था। अभिनेत्री ने बताया कि उनकी टीम को पता भी नहीं था कि वह इस बारे में कुछ बोलेंगी। बयान देने के बाद वह खुद भी पैनिक हो गई थीं। उन्हें डर था कि कहीं उनके बयान से बवाल न मच जाये। मशेबल इंडिया के साथ बातचीत में जाह्नवी कपूर ने कहा, ष्उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद, मैंने अपने पीआर को देखा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है और उन्होंने कहा कि यह एक बात उठाई जा सकती है लेकिन देखते हैं। फिर अगले दिन, मैं बस घबरा गई। उन्हें डर था कि बयान की वजह से कहीं फिल्म शमिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज को लेकर दिक्कत न हो जाये। उलझ एक्ट्रेस ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि यह सही बात है या नहीं। मेरे पीआर लोग भी हाइपर होने लगे और उन्होंने पूछा कि क्या हम उस हिस्से को हटा सकते हैं? हम फालतू का अटेंशन नहीं चाहते हैं। यह थोड़ा जोखिम भरा है और उन्होंने (पब्लिकेशन) कहा नहीं, हम इसे नहीं काटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह परेशान हो गई थीं, क्योंकि पीआर टीम इसे हटाना चाहती थी। जाह्नवी कपूर ने बताया कि फिल्म निर्माता नीरज घायवान के साथ समय बिताने के बाद उन्होंने जाति भेदभाव के बारे में पढ़ने का प्रोत्साहन मिला। वह अंबेडकर के बारे में और जानने के लिए बेताब हुईं और उन्होंने अंबेडकर की किताब एनीहिलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके अंदर काफी बदलाव आया।

जय आत्मेश्वर

आध्यात्मिक यात्रा

फुर्सत ना मिलेगी, इस दुनिया से,
जुड़ पाओगे कब, भीतर चेतना से।
निभा लूँ जिम्मेदारी, इंतजार न कर,
जुड़ जाएँ इसी, गुरु पूर्णिमा से।।

वह कर्ता करेगा,सबकुछ नियंत्रित,
राह पे रखदो, एक पग व्यवस्थित।
यात्रा निर्णय, आपके है हाथ,
सोंचो नहीं करो, क्रिया में परिणित।

बहुत कुछ कह दिया, गुरु ईश्वर ने,
लिखवाया लिख दिया, श्रीधर ने।
आपकी बारी, अब लो निर्णय,
चलो या रखदो, बन्द बिस्तर में।।

छूट जाएँगी सारी, बुरी आदतें,
बाहर से न करो, खुद पर प्रहार।
सतत करते रहो, समर्पित हो ध्यान,
परमात्मा कृपा करें,सब प्रकार।।

आध्यात्मिक यात्रा, विवरण अनंत,
मुझमें है कहाँ, ताकत लिख सकूँ।
सद्गुर ने लिखाया, लिख दिया हूँ,
धन्यवाद उन्हें, मैं उनका माध्यम हूँ।

समस्या जो ना होती, सिर सवार,
पूछता क्यों, समाधान को संसार।
सांसारिक द्वंद तो, निश्चित है,
उलझे नहीं ध्यानी, हो जाए पार।।

आत्मिक प्रगति पे, निर्भर करता,
कैसा होगा अपना, जीवन प्रवास।
समाधान,स्वीकारी भाव, के साथ,
ध्यानी करता, सर्वांगीण विकास।।

अनुभूति प्रधान, ध्यान का संस्कार,
होगा भीतर अपने, ज्ञान का संचार।
समर्पण कर, सानिध्य में सद्गुरु के,
गुरुपूर्णिमा पर, लेलो इस बार।।

सागर से वाष्पित, बूँदें हम,
चलो मिल जाएँ, अपने सागर में।
सद्गुर कृपा से, होगा आसान,
रम जाएँ, उनकी कृपा आगर में।।

आध्यात्मिक यात्रा, हो मंगलमय,
समर्पण की राह, हो जाए आसान।
प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से,
हम सब पे कृपा करें, कृपानिधान।।

—आत्मिक श्रीधर

स्रोत— सद्गुरु कृपा

राष्टीय नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए पार्टी की गाइड लाइन

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के राष्टीय नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए पार्टी की गाइड लाइन, कार्यक्रम ,राष्टीय नेतृत्व के नेता स्व नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री , इंद्रा गांधी, राजीव गांधी व पार्टी व देश के लिए किया गया योगदान उनके संदेश को जन जन में पहुंचने की आवश्यकता है पार्टी के प्रति आस्था कायम रखनी चाहिए ताकि भविष्य में पार्टी मजबूत होगी , छूट भाया नेताओ की चापलूसी नही करनी चाहिए यह तो अपने स्वार्थ के रात को ही पार्टी छोड़ कर चले जायेंगे । जो भी लोग व्यक्तिगत नेता के नाम पर राजनीति करते है ऐसे लोग ही पार्टी में गुटबाजी की राजनीति से पार्टी को कमजोर करते है ऐसे लोगो से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सचेत रहना चाहिए यही पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता की पहचान है।

एक चिंतन बाबूराम चौधरी

चार सालों में 40 वर्ष की विकास की गंगा बहाई है

बड़वानी जिले के पार्टी विकासखंड के छोटे से गांव ढान के आदरणीय डॉक्टर सुमरसिंह जी सोलंकी ने 22 जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी उनके कार्यकाल में स्वर्णिम सफलतम 4 साल आज पूर्ण हो गए हैं उन्होंने निमाड़ के लिए इन चार सालों में 40 वर्ष की विकास की गंगा बहाई है शपथ लेने के साथ उन्होंने शपथ का ईमानदारी से पालन किया और उन्होंने निमाड़ वह प्रदेश में संसद क्षेत्र विकास निधि से करोड रुपए की राशि खर्च की है जिसमें बड़वानी सहित प्रदेश के 6 से अधिक जिलों में शासकीय विद्यालय भवन विभिन्न समाजों के लिए मांगलिक भवन एंबुलेंस पुलिया सोलर लाइट धार्मिक स्थल पर टिन सेट एवं सूखे पड़े गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए टैंकरों का वितरण किया गया इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना को पूर्ण करने की मांग के संबंध में जनजाति आकांक्षी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में जिले में पहली बार संभाग स्तर पर होने वाली नीट एवं पीएससी की मुख्य परीक्षाओं का केंद्र बड़वानी में खोला गया ऐसी 100 से 200 मुद्दे उन्होंने ध्यान में रखते हुए उसे पर अमल करवाया नगर परिषद पानसेमल की ओर से शुभकामनाएं।

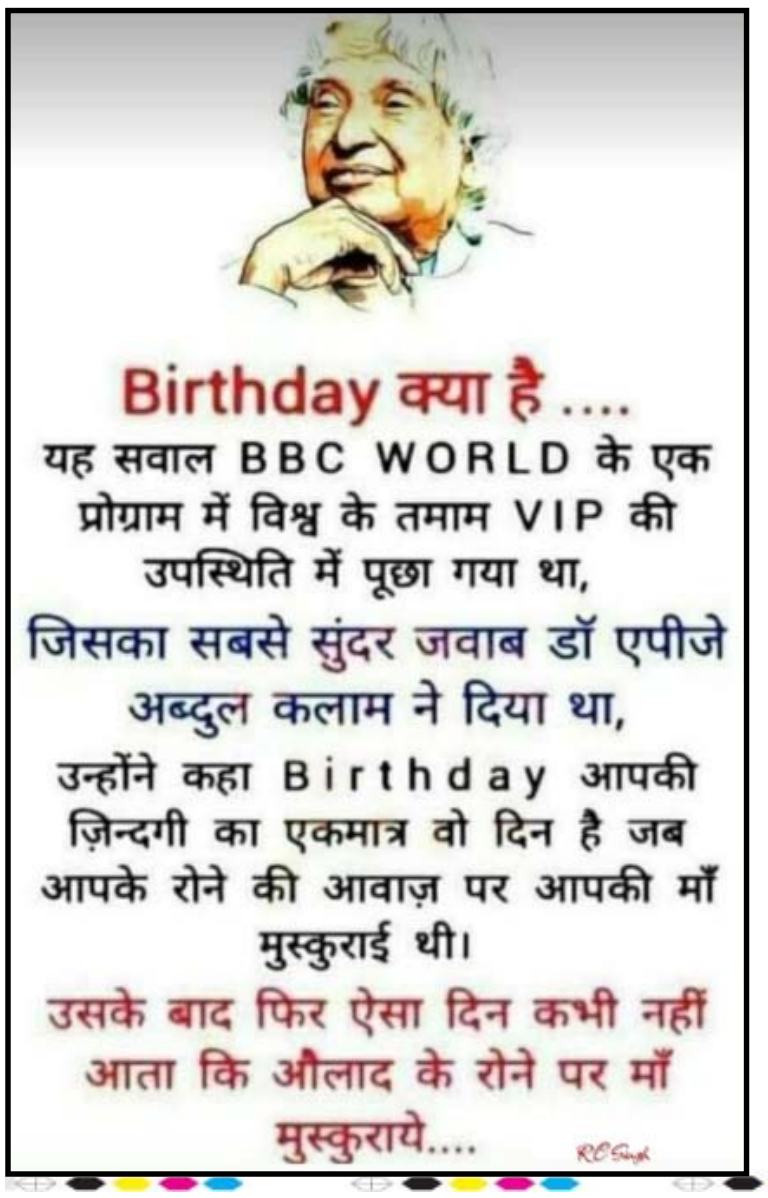

मथुरा–वृंदावन के ये 5 प्रसिद्ध मंदिर, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है, इन मंदिरों का दर्शन करें

भारत में कई प्रमुख तीर्थ स्थालों में से एक है श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा भी शामिल है। यहां हर दिन हजारों श्रृद्धालु मथुरा के मंदिरों में भगवान की एक झलक देखने के लिए आते हैं। दरअसल, मथुरा में भगवान कृष्ण को समर्पित एक से एक मंदिर स्थित है, जहां की आधुनिक निर्माण शैली और वास्तुकला दुनियाभर में मशहूर है। अगर आप भी मथुरा–वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 मंदिरों के दर्शन करना न भूले।

बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन

अगर आप भगवान कृष्ण का बाल स्वरुप देखना चाहते हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहां भगवान कृष्ण की मुख्य मूर्ति बहुत ही सुंदर है और भक्तों को बहुत ही प्रिय है। कभी आप चले जाओ इस मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहती है। खासतौर पर जन्माष्टी और होली के दौरान यहां भव्य उत्सव मनाया जाता है।

द्वारकाधीश मंदिर, मथुरा

यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है, द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली पर आधारित है। इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन तो मिलेंगे ही, साथ उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़ी कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है।

राधा रमण मंदिर, वृंदावन

इस मंदिर में भगवान कृष्ण के राधा रमण स्वरुप को समर्पित है। यह मंदिर और इसकी मूर्ति बेहद ही प्राचीन है और आकर्षक है। इस मंदिर की आरती और भजन संध्या में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा

यह तो अब हर कोई जानता है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में ही स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के गर्भगृह में ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, जो पहले कारागृह था। इस मंदिर में कान्हा जी के बालस्वरुप के दर्शन मिलते हैं। इस मंदिर को काफी खूबसूरती से बनाया गया है। यहां पर कृष्ण की सफेद मार्बल से बनी मूर्ति है, जिसके दर्शनक के लिए भक्तों की भीड़ सैदव रहती है।

जय आत्मेश्वर

आजकी प्रार्थना

सबका हो भला, सब की उन्नति,
सबका हो जाए, सर्वांगीण विकास।
सुनो आज मेरी, प्रार्थना प्रभु जी,
सबके हीय जगे, आत्मिक प्रकाश।।

—आत्मिक श्रीधर

एंडी मरे ने किया संन्यास का ऐलान, यहां खेलेंगे करियर का आखिरी टूर्नामेंट

पेरिस ओलंपिक की शुरुआत से पहले ब्रिटेन के टेनिस स्टार एंडी मरे ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, एंडी ने संन्यास की घोषणा की है। दो बार ओलंपिक पुरुष एकल चौंपियन एंडी मरे ने मंगलवार को पुष्टि की है कि पेरिस ओलंपिक के बाद वह खेल से संन्यास लेंगे। 37 वर्षीय मरे ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। वहीं एंडी मरे ने एक्स पर लिखा कि, अपने आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंच गया

हूं, पेरिस ओलंपिक में टेनिस स्पर्धा रोलां गैरो पर शनिवार से शुरू होंगी। बता दें कि, मरे ने पहला गोल्ड मेडल 2012 लंदन ओलंपिक में ग्रासकोर्ट पर जीता था जिसमें उन्होंने रोजर फेडरर को तीन सेटों में हराया था इसके बाद 2016 में रियो दि जिनेरियो में हार्डकोर्ट पर जुआन मार्टिन देल पोत्रो को हराकर खिताब अपने नाम किया था।

खूबसूरत साड़ी पहन रश्मिका मंदाना ने कैमरे के सामने दिए किलर पोज, हॉट अदाओं से इंटरनेट पर बरपाया कहर

साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीना रश्मिका मंदाना आए दिन अपनी हॉट फोटोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती रहती हैं। उनका हर एक अंदाज सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टा पर पोस्ट कर फैंस को दीवाना बना दिया है। उनके इस लुक पर से फैंस की नजरें हट पाना मुश्किल हो गई है।

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना आए दिन अपनी लेटेस्ट पोस्ट फैंस के बीच शेयर कर अक्सर लाइमलाइट बटौरती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर पोस्ट होते ही छा जाता है।

हाल ही में एक्ट्रेस के लेटेस्ट एथनिक लुक में फोटोज

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में उनका कातिलाना अवतार देखकर फैंस लट्टू हो गए हैं।

रश्मिका मंदाना ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत नजर आ रही थीं।

कानों में इयररिंग्स, बालों में गजरा और लाइट मेकअप कर के एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने आउटलुक को कंप्लीट किया है।

एक्ट्रेस ने अपनी इस साड़ी के साथ ब्लू कलर का स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ है जोकि उन पर काफी जंच रहा है।

रश्मिका मंदाना ने जिस तरह से अपने आउटफिट को कैरी किया है वो बेहद ही लाजवाब है। एक्ट्रेस जब भी अपनी पोस्ट शेयर करती हैं तो फैंस उनकी फोटोज पर दिलखोलकर लाइक्स और कॉमेंट्स करती हैं।

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रश्मिका मंदाना की इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग लिस्ट काफी तगड़ी है।

जाह्नवी कपूर की फिल्म उलझ का पहला गाना शौकन हुआ रिलीज, टाइट गाउन में अभिनेत्री ने दिखाई कातिल अदाएं

राजकुमार राव के साथ मिस्टर एंड मिसेज माही की सफलता के बाद अब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर फिल्म उलझ के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं।फिल्म के निर्देशन की कमान सुधांशु सरिया ने संभाली है। रोशन मैथ्यू, गुलशन देवैया और आदिल हुसैन जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।हाल ही में फिल्म का ट्रेलर सामने आया था। अब उलझ का पहला गाना शौकन रिलीज हो गया है, जिसमें जाह्नवी नशे में झूमती नजर आ रही हैं।

गाने शौकन को नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल ने मिलकर गाया है। इस गाने के बोल कुमार ने लिखे हैं। शाश्वत सचदेव ने इसे कंपोज किया है। उलझ 2 अगस्त, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।बॉक्स ऑफिस पर उलझ का सामना विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट से होगी, जिसकी कहानी 2002 की गोधरा ट्रेन जलने की घटना पर आधारित है।इसके अलावा अजय देवगन की औरों में कहां दम था भी 2 अगस्त को रिलीज होगी। गाने में जान्हवी के साथ गुलशन देवैया भी हैं। दोनों एक क्लब में डांस करते हुए और काफी एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। शौकन सोनी म्यूजिक इंडिया के लेबल के तहत रिलीज किया गया है। गाने के बारे में जान्हवी ने कहा, मैं हमेशा से नेहा कक्कड़ के गानों की फैन रही हूं, और उनके साथ काम करना मेरी विश लिस्ट में शामिल था। शौकन में पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। यह गाना आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मजबूर कर देगा। यह हॉट, ग्लैमरस और ग्रूवी है। मुझे लगता है कि शाश्वत, जुबिन और नेहा ने शानदार गाना तैयार किया है।

फिल्म में जान्हवी सबसे कम उम्र की डिप्टी हाई कमिश्नर सुहाना भाटिया का किरदार निभा रही हैं। उनके सलेक्शन पर सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सुहाना की नियुक्ति में नेपोटिज्म का काफी हाथ है, क्योंकि वह एक समृद्ध परिवार से हैं। वह अपने विभाग में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मशक्कत करती हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जान्हवी लंदन एंबेसी की एक खबरी की तलाश में निकलती हैं और खुद ही उसके जाल में फंस जाती हैं। अपने ऊपर लगे देशद्रोह का आरोप हटाने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए वह उन लोगों से भी भिड़ती हैं, जिन्होंने उन्हें और उनके देश को धोखा दिया है। जान्हवी कपूर ने फिल्म का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और कैप्शन में लिखा, हर किसी के पास एक कहानी है। हर

कहानी के सीक्रेट्स हैं। हर सीक्रेट में ट्रैप है। इस उलझ को सुलझाना आसान नहीं है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और यह फिल्म दो अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ज्ञान सरोवर
(हिन्दी साप्ताहिक)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक पूजा प्रसाद पाण्डेय द्वारा नवभारत प्रेस लि. नवभारत भवन, प्लाट नं.13, सेक्टर–8, सानपाड़ा (पूर्व) नवी मुम्बई 400706 (एम.एस.) से मुद्रित तथा 11 गोकुलेश सोसायटी, पंडित मदन मोहन मालवीय रोड, मुलुण्ड (प.) मुम्बई 400080 (एम.एस.) से प्रकाशित।

सम्पादक

पूजा प्रसाद पाण्डेय

मो0– 9833567799

R.N.I.No.MAHHIN/2009/27377

Email: editor@gyansarovar.org
www.gyansarovar.org

समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों/लेखों में लेखकों तथा संवाददाताओं के अपने विचार हैं। किसी भी लेख/समाचार की जिम्मेदारी प्रकाशक/सम्पादक की नहीं होगी। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र मुम्बई न्यायालय होगा।

सोच अच्छी ख़बर सच्ची